vadsi system in those States. It is for the State Governments to implement the laws meaningfully and effectively.

खराब सड़कों के कारण नुकसान

1829. **श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 जनवरी, 1988 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "650 करोड़ लॉस ड्यू टू बैड रोड्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि पांच हजार करोड़ रुपये सड़क उद्योग में न लगाने के कारण देश को प्रति वर्ष 650 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है;

(ग) क्या सड़क दुर्घटनाओं के कारण मौतें भी अधिक हो रही हैं ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में तत्काल क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) 1980-81 मूल्य स्तर के आधार पर एक अध्ययन में यह मूल्यांकन किया गया है कि सड़क सुधार पर 5300 करोड़ रुपए का निवेश करने से प्रतिवर्ष लगभग 2000 करोड़ रुपए की बचत होगी (जिसमें सिर्फ 500 करोड़ रुपए की ईंधन बचत शामिल है) ।

(ग) और (घ) प्रति एक हजार वाहनों पर सड़क दुर्घटनाओं और मृत्यु की संख्या में उत्तरोत्तर वर्ष-दर-वर्ष कमी आई है । हाल ही में गठित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद ने अपनी जुलाई, 1987 की बैठक में राज्य सरकारों और संघ क्षेत्रीय प्रशासनों को राजमार्गों पर गश्त लगाने संबंधी व्यवस्था करने के साथ-साथ राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा परिषदें तथा जिला स्तरीय समितियां गठित करने तथा सड़क सुरक्षा उपायों की रूपरेखा तैयार करने और क्रियान्वित करने की सिफारिश की थी । ड्राइविंग लाइसेंस, वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट और यातायात उल्लंघनों के लिए कठोर दण्ड देने के संबंध में मोटर यान विधेयक में कठोर उपबंधों का भी प्रावधान किया गया है ।

Private parties for setting up of passenger amenities on National Highways

1830. SHRI ASHOK NATH VERMA: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have offered to private parties for setting up of passenger amenities on National Highways in the country, if so, what are the details thereof;

(b) the names and addresses of private parties who applied for setting up of such passenger amenities in Northern States highways and sites offered and on what terms;

(c) whether it is a fact that Government have not received good response from the Northern part of the country; if so, whether the time for reecipt of additional proposals have been extended; if so, the names and addresses of the authorities whom to apply; and

(d) whether the Government have earmarked sites for setting up of passenger amenities on highways on the Northern part of the country; if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI RAJESH PILOT): (a) to (d) It is proposed to provide passenger-oriented wayside amenities at about 100 km. intervals along high traffic density corridors of National Highways, where such facilities do not exist at Present. This